[2015] 7 एस.सी.आर. 1083

इंद्रा दलाल

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1261/2009)

29 मई, 2015

[ए.के. सिकरी और उदय उमेश ललित, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 के साथ पठित धारा 120बी - अनुबंध हत्या; आरोपी एक स्कूटर पर पीड़ित-मृतक के घर आया और उसके छाती और सिर पर गोली चलाई - इसके बाद उसने मौके पर पिस्तौल फेंकी और स्कूटर पर भाग गया - अपीलकर्ताओं-आरोपियों की पूर्व शत्रुता का आरोप - अपीलकर्ताओं के खिलाफ सजा मुख्य रूप से उनके स्वीकारोक्ति बयानों और अपीलकर्ता संख्या 1 के घर से स्कूटर की बरामदगी के आधार पर दर्ज की गई - निर्णय: ये आरोपी जब पुलिस हिरासत में थे, तब इनके स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किए गए थे- ऐसे बयान धारा 25 और 26 को देखते हुए अस्वीकार्य थे - इन सभी आरोपी/अपीलकर्ताओं द्वारा स्वीकारोक्ति बयानों के रूप में दी गई जानकारी से कोई खोज नहीं हुई - स्कूटर की बरामदगी अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में की गई - यह बरामदगी मृतक के भाई

पीडब्ल्यू-2 द्वारा दिए गए बयान के आधार पर की गई थी और इन अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए किसी भी खुलासे वाले बयानों के आधार पर नहीं - इसी प्रकार, जहां तक अपीलकर्ता-जे द्वारा कथित रूप से दिया गया स्वीकारोक्ति बयान का संबंध था, वह फिर से एक अन्य प्राथमिकी में था - इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विचारित स्थिति भी आकर्षित नहीं हुई - यहां तक कि अगर स्कूटर की बरामदगी खुलासे वाले बयान के अनुसार हुई होती, तो भी स्कूटर की बरामदगी के तथ्य को ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य माना जाता, और इससे तथाकथित स्वीकारोक्ति बयान स्वीकार्य नहीं होते जिन्हें उनके खिलाफ सिद्ध नहीं माना जा सकता - अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ साजिश का आरोप उचित रूप से साबित नहीं कर पाया - सजा रद्द की गई - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 25 से धारा 27।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 25 और 26 - इनके पीछे का दर्शन - विचार-विमर्श किया गया।

शब्द और वाक्यांश: 'स्वीकारोक्ति' - इसका अर्थ - विचार-विमर्श किया गया।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1. अभियोजन पक्ष ने एक गवाह (पीडब्लू-7) पेश किया था, जो कथित तौर पर साजिश का गवाह था। हालाँकि, मुकदमे के दौरान, उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। इसलिए इस साजिश का कोई गवाह नहीं था। इसमें कोई शक नहीं, ऐसी साजिशें आम तौर पर अंधेरे में और गुप्त रूप से रची जाती हैं और हो सकता है कि इनका कोई चश्मदीद गवाह भी न हो| इन अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुख्य रूप से उनके स्वीकारोक्ति बयानों और अपीलकर्ता संख्या 1 के घर से स्कूटर की बरामदगी के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज की गई थी और उच्च न्यायालय ने उसे बरकरार रखा था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के पीछे का दर्शन एक कठोर वास्तविकता को स्वीकार करना है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और यातना या यहां तक कि प्रलोभन देकर बयान लिए जाते हैं और इसलिए, वे किसी भी विश्वसनीयता के योग्य नहीं हैं। यह प्रावधान आरोपी के खिलाफ पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए कबूलनामे को पूरी तरह से सबूत से बाहर कर देता है। 'कन्फेशन' शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, न्यायालयों ने शब्दकोष के अर्थ का सहारा लिया है और समझाया है कि आरोपी द्वारा पुलिस को दिए गए आपत्तिजनक बयान, जो अपराध के घटित होने का अनुमान लगाते हैं, स्वीकारोक्ति के समान होगा और इसलिए, इस प्रावधान के तहत अस्वीकार्य

है। इसे अपराध की प्रत्यक्ष स्वीकृति के रूप में भी परिभाषित किया गया है, न कि किसी भी आपत्तिजनक तथ्य को स्वीकार करना, चाहे वह कितना भी गंभीर या निर्णायक क्यों न हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 उन सभी संस्वीकृति को अस्वीकार्य बनाती है जब वे किसी व्यक्ति द्वारा की जाती हैं, जबकि वह एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, जब तक कि ऐसी संस्वीकृति मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं की जाती है। इसलिए, जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है, तो उसके द्वारा पुलिस अधिकारी के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष किया गया कबूलनामा भी अस्वीकार्य हो जाएगा। वर्तमान मामले में, न केवल एक पुलिस अधिकारी के सामने स्वीकारोक्ति बयान दिए गए थे, बल्कि ऐसे स्वीकारोक्ति बयान अपीलकर्ताओं द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद भी दिए गए थे, जब वे पुलिस हिरासत में थे। निचली न्यायालयों ने इन स्वीकारोक्ति बयानों पर भरोसा किया था, साथ ही 'रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य संबंधित साक्ष्य', विशेष रूप से अपीलकर्ता के पुराने घर से स्कूटर की बरामदगी और अपीलकर्ता-जे द्वारा एक अन्य मामले में दिए गए प्रकटीकरण/स्वीकारोक्ति बयान पर, जो इंस्पेक्टर पीडब्लू-15 द्वारा साबित किए गए थे। हाई कोर्ट का यह रुख कानून के विपरीत है। [पैरा 14, 16 से 20] [1093-एफ-एच; 1094-एच; ई 1095-ए, सी-जी; 1096-जी-एच; 1097-ए-बी]

2. यह स्पष्ट है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के परंतुक के रूप में है। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्राप्त ऐसी जानकारी, जिसने किसी तथ्य का पता चला है, आरोपी के खिलाफ उपयोग की जा सकती है। दी गई ऐसी जानकारी को खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। वर्तमान मामले में, सभी अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा स्वीकारोक्ति बयानों के रूप में प्रदान की गई जानकारी से कोई खुलासा नहीं हुआ है। स्कूटर की बरामदगी का अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से दिए गए स्वीकारोक्ति बयानों से कोई संबंध नहीं है। यह बरामदगी मृतक के भाई पीडब्लू-2 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार की गई थी। यह इन अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए किसी प्रकटीकरण बयान के आधार पर नहीं था। इसी तरह, जहां तक अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर दिए गए स्वीकारोक्ति बयान का सवाल है, वह भी एक अन्य एफआईआर में है। अत: साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत विचारित स्थिति भी आकर्षित नहीं करती है। भले ही स्कूटर को प्रकटीकरण बयान के अनुसार बरामद किया गया था, इससे केवल स्कूटर की बरामदगी का तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगा, और यह अपीलकर्ताओं के तथाकथित स्वीकारोक्ति बयानों को स्वीकार्य नहीं बनाएगा

जो कि उनके ख़िलाफ़ साबित नहीं माना जा सकता [पैरा 23] [1097-एफ-एच; 1098-ए-डी] |

3. पीडब्लू-17, जांच अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि 13 जुलाई 2001 को, कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया स्कूटर अपीलकर्ता-1 के घर से बरामद किया गया था। यह स्कूटर बरामदे में खड़ी थी और उसे कब्जे में ले लिया गया। 13 जुलाई 2001 को, अपीलकर्ता-। जेल में थी, क्योंकि उसे 02 जून 2001 को गिरफ्तार किया गया था, जब तथाकथित बरामदगी की गई थी। इस प्रकार, उसकी अनुपस्थिति में बरामदगी की गई। पीडब्लू-17 घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता-1 के घर गया था, लेकिन उसे कोई स्कूटर नहीं मिला। यदि जांच के दौरान स्कूटर का पंजीकरण नंबर पीडब्लू-2 द्वारा दिया गया था और जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता-1 के घर का दौरा किया था, तो वह उस तारीख को उसी नंबर के साथ वहां पार्क किया गया स्कूटर कैसे नहीं पा सका। ये सभी तथ्य अपीलकर्ता-1 के घर से स्कूटर की कथित बरामदगी पर संदेह की छाया डालते हैं| अपीलकर्ता-जे ने इस बात से इनकार किया है कि विचाराधीन स्कूटर उसका है। अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पंजीकरण क्लर्क, पीडब्लू 18 को पेश किया था। अपीलकर्ता-जे के स्वामित्व को दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत

नहीं किए गए थे। कथित तौर पर रिकार्ड के आधार पर लिपिक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ही पेश की जाती है। वह प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। अपीलकर्ता-जे के नाम पर स्कूटर का स्वामित्व साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। सबूतों की पूरी श्रृंखला या तो साक्ष्य अधिनियम द्वारा पैदा की जाने वाली बाधा डालने के लिए अस्वीकार्य है या अविश्वसनीय/अविश्वसनीय है। अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 120-बी की सहायता से इन अपीलकर्ताओं के खिलाफ साजिश के आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। [पैरा 28 से 30] [1101-डी, ई-एच; 1102-ए-एच; 1103-ए]

बुल्लू दास बनाम बिहार राज्य (1998) 8 एससीसी 130; मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2002) 7 एससीसी 334; फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन और अन्य बनाम केरल राज्य (2001) 7 एससीसी 596; राज्य बनाम नलिनी 1999 (3) एससीआर 1 : (1999) 5 एससीसी 253 - पर निर्भर किया गया।

केस कानून संदर्भ

(1998) 8 सेकंड 130 पर निर्भर। पैरा 19

(2002) 7 एससीसी 334 पर भरोसा किया। पैरा 24

(2001) 7 एससीसी 596 पर भरोसा किया। पैरा25

1999 (3) एससीआर 1 पर भरोसा किया गया। पैरा 20

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1261/2009 आदि।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 311-डीबी/ 2008 में निर्णय और आदेश दिनांक 03.03.2009 से उत्पन्न।

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 1620/ 2009

आपराधिक अपील संख्या 1189/2011

सुशील कुमार, संजय जैन, सुदर्शन सिंह रावत, हरपुनीत सिंह राय, दया कृष्ण शर्मा, अपीलकर्ता की और से।

दीपक ठुकराल, डॉ. मोनिका गुसाईं, विश्व पाल सिंह, राजीव कुमार सिंह, प्रतिवादी की और से ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

ए.के. सीकरी, न्यायाधिपति -

1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या 99 दिनांक 24 मई 2001 को पुलिस स्टेशन: सिटी दादरी, हरियाणा में दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में नंद करण (इसके बाद 'मृतक' कहा जाएगा) की हत्या के लिए पांच लोगों को फंसाया गया और आरोपी बनाया गया। उनमें से, तीन अपीलकर्ता हमारे सामने हैं, जिन पर एक साथ मुकदमा चलाया गया और 11 अप्रैल, 2008 के फैसले के तहत सत्र न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जिसके बाद 12 अप्रैल, 2008 को सजा के आदेश के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के साथ पठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर निर्देश दिया गया कि उन्हें एक-एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। एक अन्य व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया और इन अपीलकर्ताओं के साथ मुकदमा चलाया गया। हालाँकि, उन पर लगाए गए आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। पांचवें व्यक्ति, उदयवीर उर्फ़ उदे उर्फ़ संदीप, जो उक्त आरोप-पत्र में भी आरोपी था, को उसी तारीख यानी 11 अप्रैल, 2008 को सुनाए गए एक अलग फैसले द्वारा दोषी ठहराया गया था और समान सजा दी गई थी। चारों दोषी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में

अपील की। उच्च न्यायालय ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, भिवानी द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए इन अपीलों को खारिज कर दिया। उदयवीर ने आगे कोई अपील नहीं की है। हालाँकि, इन तीन अपीलों में हमारे सामने मौजूद तीन अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर करके उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का विकल्प चुना, जिसमें पहले छुट्टी दी गई थी।

2) अब, हम संक्षेप में अभियोजन के मामले पर ध्यान देते हैं, जिसे उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त निर्णय अभियोजन पक्ष के संस्करण को सही ढंग से दर्ज करता है:

3) मृतक नंद करण, एक सेवानिवृत्त मास्टर, और उनकी पत्नी सूरज कौर, दादरी के लोहारू रोड पर स्थित 'लाल कोठी' नामक घर में रहते थे। 24 मई 2001 को रात्रि करीब 8 बजे मृतक, उसकी पत्नी तथा उसका भाई हरीश चन्द्र गोदारा घर में मौजूद थे। जब मृतक की पत्नी लॉन में पौधों को पानी दे रही थी, तो मृतक कमरे के अंदर और उसका भाई छत पर, लगभग 22-25 साल का एक युवा लड़का स्कूटर पर आया। उसने सूरज कौर को बताया कि वह रोहतक से आया है और मास्टर नंद करण से मिलना चाहता है। जब वह उस लड़के से बात कर रही थी तो मृतिका घर से बाहर गेट पर

आ गयी. सूरज कौर ने मृतक को बताया कि एक लड़का उससे मिलने आया था. इसके तुरंत बाद, लड़के ने अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकाली और मृतक की छाती पर गोली मार दी। मृतक के सिर में एक और गोली मारी गई और वह चिल्लाते हुए गिर पड़ा| गोली चलने की आवाज सुनकर मृतक का भाई हरीश चंद्र गोदारा तुरंत मौके पर आए। पिस्तौल को घटनास्थल पर फेंकने के बाद लड़का जिस स्कूटर पर आया था, उसी पर बैठकर भाग गया। घटना के बाद सुरेश कुमार, होशियार सिंह के पुत्र, और जयपाल, कमल सिंह के पुत्र सहित कई लोग, मौके पर पहुंचे। वाहन की व्यवस्था कर वे मृतक को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में मृतक की देखभाल करने वाले डॉ. एच.एल. बेनीवाल (पीडब्लू-3) ने उसे मृत घोषित किया और रात 9.10 बजे दादरी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को सुरेश कुमार और जयपाल द्वारा लाए गए शव के संबंध में एक रुक्का (प्रदर्शनी पीई) भेजा।

4) अस्पताल में, सूरज कौर (एक्ज़िबिट पीए) का बयान 24 मई 2001 को रात 11.00 बजे सब-इंस्पेक्टर राम चंदर (पीडब्लू-17) द्वारा दर्ज किया गया था। अपने बयान में उसने उपरोक्त घटना बताई और आगे कहा कि उसके पति की हत्या डॉ. इंद्रा दलाल, उसके भाई बिजेंद्र उर्फ विजय और महाबीर ने किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से साजिश रचकर करवाई है।

जैसा कि उन्होंने बताया, शिकायत का कारण यह था कि उन्होंने उनके पति, उनके बेटे रविंदर कुमार और एक बेटे संदीप के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। महाबीर सिंह और उस संबंध में आईपीसी की धारा 302 के तहत एक आपराधिक मुकदमा लंबित था। हालाँकि, उनके पति को लगभग तीन महीने पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उक्त रंजिश के चलते इंद्रा दलाल, उसके भाई बिजेंद्र उर्फ विजय और महाबीर ने एक साजिश के तहत सुपारी किलर को बुलाकर उसके पति की हत्या कर दी। उक्त बयान के आधार पर 24 मई 2001 को रात 11.10 बजे पुलिस स्टेशन दादरी में एफआईआर (प्रदर्श पीए/1) दर्ज की गई थी। उक्त एफआईआर की विशेष रिपोर्ट 25 मई 2001 को रात्रि 12.30 बजे क्षेत्राधिकारी को प्राप्त हुई।

5) 25 मई 2001 को मृतक का पोस्टमार्टम डॉ. अनिल चौधरी (पीडब्लू-4), डॉ. एच.एल. बेनीवाल और डॉ. गिरि राज द्वारा किया गया। उन्हें मृतक के शरीर पर बंदूक की गोली के दो घाव मिले, एक छाती पर और दूसरा मस्तिष्क पर। उन चोटों से एक-एक फूस निकलवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्ज़िबिट पीएफ) में मृतक की मौत का कारण रक्तस्राव और महत्वपूर्ण अंगों पर बंदूक की गोली की चोट के कारण सदमा बताया गया।

6) अभियोजन का मामला, इस प्रकार, संक्षेप में यह है: एक दीपेंद्र @ बंटी, जो अपीलकर्ता इंद्र दलाल का बेटा और बिजेंदर का भतीजा था, की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक नंद करण को उसके बेटों, रविंदर के साथ फंसाया गया था। कुमार और संदीप, जो उस सिलसिले में जेल में भी थे। बदला लेने के लिए, अपीलकर्ता इंद्रा दलाल और उसके भाई बिजेंद्र और महाबीर ने नंद करण को मारने की साजिश रची थी, जिसके लिए उन्होंने उदयवीर को बहकाया और उसके माध्यम से उसकी हत्या करवा दी।

7) उपरोक्त एफआईआर के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान सुरेश और हरीश चंदर गोदारा के बयान दर्ज किए गए. हरीश चंद्र गोदारा ने बताया कि जिस स्कूटर पर हमलावर उदयवीर आया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR 20G 1102 है। मृतक के कपड़े, एक चली हुई गोली, चली हुई गोली का एक कारतूस सहित कुछ अन्य सामान जब्त किया गया है, जिस पर सी.एफ.एल. रिपोर्ट प्राप्त हुई. मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

8) 31 मई 2001 को अपीलकर्ता बिजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कथित तौर पर मृतक की हत्या के लिए उपरोक्त साजिश और मकसद को स्वीकार करते हुए एक खुलासा/स्वीकारोक्ति बयान (प्रदर्शनी पीएच) दिया। 02 जून 2001 को, अपीलकर्ता इंद्रा दलाल को गिरफ्तार किया गया और उसने भी इसी तरह का खुलासा/स्वीकारोक्ति बयान दिया (प्रदर्शनी

पीटी)। उसी दिन, बिजेंदर द्वारा एक और स्वीकारोक्ति बयान (एक्ज़िबिट पीके) दिया गया था।

9) जांच के अनुसार, पुलिस ने प्रदीप कुमार पुत्र का बयान दर्ज किया। 07 जुलाई 2001 को दया नंद, जो चरखी दादरी के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि 27 मई 2001 को वह अपनी पत्नी के मेडिकल चेकअप के लिए अपीलकर्ता इंद्रा दलाल के क्लिनिक में गए थे। उसी समय बिजेंद्र वहां आया और दोनों अपीलकर्ता अंदर चले गए। जब वह कुछ देर तक बाहर नहीं आई, तो प्रदीप कुमार दरवाजे के पास गए, जो थोड़ा खुला था, और दोनों अपीलकर्ताओं की बातचीत सुनी, जिसके अनुसार बिजेंद्र·इंद्र दलाल को बता रहा था कि उसने नंद करण की हत्या के लिए उदयवीर को शामिल किया था। जांच के दौरान, 13 जुलाई 2001 को रिकवरी एक्ज़िबिट पीडी के माध्यम से इंद्र दलाल के पुराने घर से एक क्रीम रंग का एलएमएल स्कूटर, जिसका पंजीकरण नंबर एचआर 20 जी 1102 था, बरामद किया गया था।

10) इसके बाद, दूसरे अपीलकर्ता जयबीर को 10 दिसंबर 2001 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने भी अपना खुलासा/स्वीकारोक्ति बयान (एक्ज़िबिट पीएल) उसी प्रभाव से दिया था, जैसा कि अन्य दो अपीलकर्ता इंद्र दलाल और बिजेंद्र ने दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उस उद्देश्य के लिए उदयवीर और रमेश को स्कूटर दिया था। रमेश का नाम बताने पर

उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसी तर्ज पर 23 दिसंबर 2001 को उसका खुलासा/स्वीकारोक्ति बयान (प्रदर्शनी पीओ) दर्ज किया गया। जांच के बाद, उदयवीर को छोड़कर इन आरोपियों के खिलाफ चालान दायर किया गया, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। हालाँकि, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, उदयवीर को भी 07 फरवरी, 2004 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका खुलासा/स्वीकारोक्ति बयान (एक्ज़िबिट पीएन) भी दर्ज किया गया था।

11) मुकदमे के दौरान, इन अपीलकर्ताओं और रमेश के खिलाफ दायर चालान/मामले में, अभियोजन पक्ष ने अठारह गवाहों की जांच की। इनमें सूरज कौर-शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1), जिन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया, हरीश चंदर गोदारा, मृतक के भाई (पीडब्लू-2), जिन्होंने अभियोजन संस्करण का भी समर्थन किया था, डॉ. एच.एल. बेनीवाल (पीडब्लू-3), जिन्होंने थाना दादरी के थाना प्रभारी, डॉ. अनिल चौधरी (पीडब्लू-4), जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था, और प्रदीप कुमार (पीडब्लू-7), जो कथित गवाह थे, को रुक्का (प्रदर्शनी पीई) भेजा था। साजिश का, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अन्य गवाह ज्यादातर पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने इन आरोपी व्यक्तियों के साथ-साथ जांच करने

वाले जांच अधिकारी के किसी न किसी खुलासे/स्वीकारोक्ति बयान को साबित किया। गुलाब सिंह (पीडब्लू-18), क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पंजीकरण क्लर्क, को भी पेश किया गया, जिन्होंने बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार, जयबीर पुत्र कांशी राम, उस स्कूटर के मालिक थे जिसे पुलिस ने जब्त किया था। आरोपियों के बयान जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए थे, में उन सभी ने बताया कि वे निर्दोष थे और इस मामले में झूठे आरोपों में फंसाए गए थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके स्वीकारोक्ति बयान उन पर दबाव डालकर इंद्रा दलाल के बेटे की हत्या के मामले को सुलझाने के लिए दर्ज किए गए थे।

12) आरोपी उदयवीर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने सत्रह गवाहों की जांच की। हालाँकि, चूंकि उदयवीर ने कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए हम उसके खिलाफ सामने आने वाले सबूतों से संबंधित चर्चा से बच रहे हैं।

13) जांच के अनुसार, पुलिस ने प्रदीप कुमार पुत्र दया नंद का बयान 07 जुलाई 2001 को दर्ज किया, जो चरखी दादरी के निवासी थे। उन्होंने कहा कि 27 मई 2001 को वह अपनी पत्नी के मेडिकल चेकअप के लिए अपीलकर्ता इंद्रा दलाल के क्लिनिक में गए थे। उस समय बिजेंदर वहां आया और दोनों अपीलकर्ता अंदर चले गए। जब वह कुछ देर तक बाहर नहीं आई,

तो प्रदीप कुमार ने थोड़ा खुले दरवाजे के पास जाकर दोनों अपीलकर्ताओं की बातचीत सुनी, जिसके अनुसार बिजेंदर इंद्रा दलाल से कह रहा था कि उसने नंद करण की हत्या के लिए उदयवीर को शामिल किया था। जांच के दौरान, 13 जुलाई 2001 को इंद्रा दलाल के पुराने घर से एक क्रीम रंग का एलएमएल स्कूटर, जिसका पंजीकरण नंबर एचआर 20 जी 1102 था, बरामद किया गया था, जिसे रिकवरी एक्ज़िबिट पीडी के माध्यम से बरामद किया गया था।

14) जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभियोजन पक्ष ने एक गवाह, प्रदीप कुमार (पीडब्लू-7) को पेश किया था, जो कथित तौर पर साजिश का गवाह था। हालाँकि, मुकदमे के दौरान, उन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। इसलिए इस साजिश का कोई गवाह नहीं है. इसमें कोई शक नहीं, ऐसी साजिशें आम तौर पर अंधेरे में और गुप्त रूप से रची जाती हैं और हो सकता है कि इनका कोई चश्मदीद गवाह भी न हो। हमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य या पेश किए गए अन्य साक्ष्यों से यह देखना होगा कि ऐसा आरोप स्थापित होता है या नहीं. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज की गई है और उच्च न्यायालय द्वारा इन अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुख्य रूप से उनके स्वीकारोक्ति बयान और इंद्र दलाल के घर से स्कूटर की बरामदगी के आधार

पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है। इसलिए, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे बयानों के आधार पर दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है।

15)अपीलकर्ता इंद्र दलाल और बिजेंद्र की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुशील कुमार ने तर्क दिया कि ये स्वीकारोक्ति बयान इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए थे और जब ये आरोपी पुलिस हिरासत में थे। इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 और 26 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बयान अस्वीकार्य थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 कुछ निश्चित और स्पष्ट शब्दों में ऐसा आदेश देती है, जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> "25. पुलिस अधिकारी को दिया गया स्वीकारोक्ति बयान साबित नहीं किया जाएगा। - किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान साबित नहीं किया जाएगा।"
>
> इसी तरह, धारा 26 ऐसे किसी भी बयान को अस्वीकार्य बनाती है जो पुलिस हिरासत में दिया गया हो। यह पढ़ता है:

"26. पुलिस की हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति बयान उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। - किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किया गया कोई भी कबूलनामा, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न किया गया हो, साबित नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध.

स्पष्टीकरण- इस धारा में 'मजिस्ट्रेट' में मजिस्ट्रियल कार्यों (फोर्ट सेंट जॉर्ज या अन्यत्र के प्रेसीडेंसी में) का निर्वहन करने वाले गांव के मुखिया को शामिल नहीं किया गया है, जब तक कि ऐसा मुखिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1882 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो।"

16) उपरोक्त प्रावधान के पीछे का दर्शन एक कठोर वास्तविकता को स्वीकार करना है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और यातना या यहां तक कि प्रलोभन देकर अपराध स्वीकार किए जाते हैं और इसलिए, वे किसी भी विश्वसनीयता के योग्य नहीं हैं। यह प्रावधान अभियुक्त के खिलाफ पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए कबूलनामे को पूरी तरह से सबूत से बाहर कर देता है। यह प्रावधान उन स्वीकारोक्ति पर भी लागू होता है जो किसी पुलिस

अधिकारी को दी जाती हैं जो अन्यथा ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। यदि वह एक पुलिस अधिकारी है और उसकी उपस्थिति में, किसी भी क्षमता में, अपराध स्वीकारोक्ति की गई है, तो वह साक्ष्य में अस्वीकार्य हो जाता है। यह इस प्रावधान के तहत निहित कानून का मूल नियम है और इस सख्त नियम को इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों द्वारा भी अनगिनत बार दोहराया गया है।

17) स्वीकारोक्ति' शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, न्यायालयों ने शब्दकोष के अर्थ का सहारा लिया है और समझाया है कि आरोपी द्वारा पुलिस को दिए गए आपत्तिजनक बयान, जो अपराध के घटित होने का अनुमान लगाते हैं, स्वीकारोक्ति के समान होगा और इसलिए, इस प्रावधान के तहत अस्वीकार्य है। इसे अपराध की प्रत्यक्ष स्वीकृति के रूप में भी परिभाषित किया गया है, न कि किसी भी आपत्तिजनक तथ्य को स्वीकार करना, चाहे वह कितना भी गंभीर या निर्णायक क्यों न हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 उन सभी संस्वीकृति को अस्वीकार्य बनाती है जब वे किसी व्यक्ति द्वारा की जाती हैं, जबकि वह एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, जब तक कि ऐसी संस्वीकृति मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं की जाती है। इसलिए, जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है,

तो उसके द्वारा पुलिस अधिकारी के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष किया गया कबूलनामा भी अस्वीकार्य हो जाएगा।

18) वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, न केवल एक पुलिस अधिकारी के सामने बयान दिए गए थे, ऐसे स्वीकारोक्ति बयान अपीलकर्ताओं द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद दिए गए थे जब वे पुलिस हिरासत में थे। 'बुल्लू दास बनाम बिहार राज्य' (1998) 8 एससीसी 130 (2002) 7 एससीसी 334 में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्तों द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयानों से निपटते समय, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "7. अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्वीकारोक्ति बयान, उदाहरण 5, गोड्डा टाउन पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया था, जहां कुसुम देवी की हत्या के संबंध में अपराध दर्ज किया गया था। एफआईआर 8 अगस्त 1995 को दोपहर के करीब 12.30 बजे पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद, 9 अगस्त 1995 को, अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के पश्चात् जब उसे राकेश कुमार के समक्ष लाया गया, तब उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि बचाव पक्ष की ओर

से इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं की गई। विचारण न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि इस तरह का स्वीकारोक्ति बयान सबूत के तौर पर स्वीकार्य है या नहीं। हाई कोर्ट ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया है। स्वीकारोक्ति बयान स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था क्योंकि यह जांच शुरू होने के बाद एक आरोपी द्वारा एक पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया था।"

19) फिर भी, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इन स्वीकारोक्ति बयानों पर, इन बयानों के आधार पर, साथ ही 'रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य संबंधित साक्ष्य' के आधार पर भरोसा किया, विशेषकर आरोपी इंद्रा दलाल के पुराने घर से स्कूटर की बरामदगी और जयबीर द्वारा एक अन्य मामले में दिया गया खुलासा/ स्वीकारोक्ति बयान (मार्क ए), जो फायर रिपोर्ट नंबर 718 दिनांक 30 नवंबर 2001, धारा 420, 407, 463, 471, 120-बी आईपीसी और आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25, 54, 59 के तहत हिसार के सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, को इंस्पेक्टर रामअवतार (पीडब्लू-15) द्वारा साबित किया गया है।

20) उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क से यह पता चलता है कि स्वीकारोक्ति बयान अन्य सबूतों के साथ समर्थित थे। इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने 'अन्य जुड़े सबूतों' का उल्लेख किया है, लेकिन हमें स्कूटर की बरामदगी और एफआईआर नंबर 718 दिनांक 30 नवंबर 2001 के जयबीर द्वारा दिए गए खुलासे/स्वीकारोक्ति बयान (मार्क एए) पर भरोसा किया गया है। उच्च न्यायालय ने किसी अन्य साक्ष्य का नाम नहीं लिया है। हमारे द्वारा राज्य के वकील से की गई विशिष्ट पूर्णग्रांथ पर प्रश्न करने पर, उन्होंने भी स्वीकार किया कि केवल 'रिकॉर्ड पर उपलब्ध एकमात्र संबंधित साक्ष्य' वह था जिसमें स्कूटर की बरामदगी और एफआईआर नंबर 718 दिनांक 30 नवंबर 2001 के जयबीर द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान (मार्क एए) शामिल था। उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को, जिसमें अन्यथा अस्वीकार्य स्वीकारोक्ति बयानों पर 'अन्य जुड़े साक्ष्यों' के साथ निर्भर किया जा रहा है, कानून के खिलाफ माना जा सकता है। हम इस प्रकार के अप्राप्य दृष्टिकोण पर आपराधिक दंडन को इस तरह के विचार पर संदेह करते हैं, जो कानून में प्राप्ति नहीं है। हम इस निष्कर्ष को मजबूती देते हैं जैसे-जैसे हम कानूनी सिद्धांतों के और इसके तथ्यात्मक प्रतिष्ठापन पर चर्चा करते हैं।

21) सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ताओं के स्वीकारोक्ति बयानों पर विश्वास करने के लिए इन्हें ध्यान में रखा जा सकता है, जो अन्यथा कानून में अस्वीकार्य थे।

22) स्वीकारोक्ति बयानों में निहित जानकारी का एकमात्र भाग जिसे साबित किया जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "27. आरोपी से प्राप्त कितनी जानकारी साबित की जा सकती है। बशर्ते कि, जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप कोई भी तथ्य खोजा गया हो, तो इतनी जानकारी ऐसी जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, साबित की जा सकती है।"

23) यह स्पष्ट है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के परंतुक के रूप में है। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्राप्त ऐसी बहुत सी जानकारी, जिसके कारण किसी तथ्य का पता चला है, का उपयोग आरोपी

के खिलाफ किया जा सकता है। प्रस्तुत की गई जानकारी को उस तथ्य से सीधे तौर पर जोड़ा जाना चाहिए जिसकी खोज की गई है। इस मामले में, जो स्वीकारोक्ति बयान सभी आरोपियों/अपीलकर्ताओं ने दिए हैं, उनसे किसी भी नए तथ्य का पता नहीं चला है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो, जिस स्कूटर की बरामदगी हुई है, उसका अपीलकर्ताओं के द्वारा दिए गए कथित स्वीकारोक्ति बयानों से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह बरामदगी हरीश चंदर गोदारा के बयान के अनुरूप हुई। यह इन अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए किसी प्रकटीकरण बयान के आधार पर नहीं था। इसी तरह, जहां तक कथित तौर पर जयबीर द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान (मार्क ए) का सवाल है, वह भी एक अन्य एफआईआर में है। हम इसकी स्वीकार्यता पर अलग से विचार करेंगे। अत: साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत विचारित स्थिति भी आकर्षित नहीं करती है। भले ही स्कूटर को प्रकटीकरण बयान के अनुसार बरामद किया गया था, इससे केवल स्कूटर की बरामदगी का तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगा, और यह अपीलकर्ताओं के तथाकथित स्वीकारोक्ति बयानों को स्वीकार्य नहीं बनाएगा जो कि उनके ख़िलाफ़ साबित नहीं माना जा सकता|

24) इस समय, आइए चर्चा करें कि क्या अपीलकर्ता जयबीर द्वारा किसी अन्य मामले में किया गया खुलासा/स्वीकारोक्ति बयान (मार्क ए)

साजिश के आरोप को साबित करने के लिए प्रासंगिक होगा। यह बताना प्रासंगिक होगा कि जयबीर ने यह बयान उस घटना के काफी बाद दिया है, जब स्वाभाविक रूप से, सामान्य इरादे का अस्तित्व समाप्त हो गया था। केवल इस आधार पर यह स्वीकार्य नहीं होगा। हम मोहम्मद मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना चाहेंगे। मो. खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1998) 8 एससीसी 130 (2002) 7 एससीसी 334, जिसमें इस न्यायालय ने कहा:

> "33. स्वीकारोक्ति बयान के संदर्भ में हमारे द्वारा उल्लिखित बातों के आधार पर, यह जांचना आवश्यक नहीं है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान को विश्वसनीयता प्रदान की जानी चाहिए, यहां तक कि अगर टाडा अधिनियम की धारा 15 के अनुसार स्वीकारोक्ति बयान दर्ज नहीं किया गया हो। हालांकि, हम आरोपी-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के रुख में तथ्य पाते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10, जो सामान्य नियम का अपवाद है, वह एक साजिशकर्ता द्वारा दिए गए बयान को अन्य साजिशकर्ता के खिलाफ स्वीकार्य होने की अनुमति देते हुए, इसे केवल उस अवधि के दौरान दिए गए बयानों तक

सीमित करता है, जब एजेंसी का अस्तित्व था। गुजरात राज्य बनाम मोहम्मद अतीक [(1998) 4 सेकंड 351] मामले में यह माना गया था कि अब यह सिद्धांत अनसुलझा नहीं रहा है कि गिरफ्तारी के बाद किसी आरोपी द्वारा दिया गया कोई भी बयान, चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या अन्यथा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के दायरे में नहीं आ सकता है। एक बार जब सामान्य इरादे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद पूर्व साजिशकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी बयान को उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में दिया गया बयान नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के बाद दिया गया बयान, चाहे वह कबूलनामा हो या साजिश में उसकी संलिप्तता को छूता हो, साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के दायरे में नहीं आएगा।

25) इसी तरह, फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन और अन्य बनाम केरल राज्य (2001) 7 एससीसी 596 मामले में, इस न्यायालय ने साजिश के कानून पर व्यापक चर्चा की और वहां से प्राप्त निम्नलिखित अंश आईपीसी की धारा 120-ए और 120-बी में निहित कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे।"

"25. षडयंत्र न केवल एक वास्तविक अपराध है, यह उन मामलों में एक व्यक्ति को दूसरों के अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराने के आधार के रूप में भी कार्य करता है, जहां मिलीभगत के सामान्य सिद्धांतों का अनुप्रयोग उस व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाएगा। इस प्रकार, जो कोई षडयंत्रकारी रिश्ते में प्रवेश करता है, वह षडयंत्र के प्रत्येक अन्य सदस्य द्वारा अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हर उचित रूप से पूर्वानुमानित अपराध के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह अपराधों के बारे में जानता हो या नहीं या उनके कमीशन में सहायता की हो। तर्क यह है कि किसी साजिश को आगे बढ़ाने में किए गए आपराधिक कार्य समूह के प्रोत्साहन और समर्थन पर पर्याप्त रूप से निर्भर हो सकते हैं ताकि प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक कार्य के लिए एक आकस्मिक एजेंट के रूप में माना जा सके। इस दृष्टिकोण के तहत, किस साजिशकर्ता ने वास्तविक अपराध किया, यह प्रतिवादी के दायित्व को निर्धारित करने में इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण होगा कि अपराध श्रम के एक बड़े विभाजन

के एक भाग के रूप में किया गया था जिसमें अभियुक्त ने भी अपने प्रयासों का योगदान दिया था।

26. साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में, साजिश के मुकदमे में मानकों को ढीला कर दिया गया है। सामान्य नियम के विपरीत; साजिश के मुकदमों में, एक साजिशकर्ता द्वारा की गई कोई भी घोषणा, एक साजिश को आगे बढ़ाने में और उसके लंबित रहने के दौरान, प्रत्येक सहसाजिशकर्ता के खिलाफ स्वीकार्य होती है। सुनी-सुनाई बातों के सबूतों की अविश्वसनीयता के बावजूद, यह साजिश के मुकदमों में स्वीकार्य है। इस नियम को समझाते हुए जज हैंड ने कहा:

"ऐसी घोषणाएँ साक्ष्य के कानून के किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि अपराध के वास्तविक कानून पर स्वीकार की जाती हैं। जब पुरुष किसी गैरकानूनी अंत के लिए एक समझौते में प्रवेश करते हैं, तो वे एक दूसरे के लिए तदर्थ एजेंट बन जाते हैं, और 'अपराध में साझेदारी' कर लेते हैं। जो कुछ भी एक व्यक्ति उनके सामान्य उद्देश्य के अनुसार करता है, उसे सभी माना जाता है, और चूंकि घोषणाएँ ऐसे कृत्य हो सकती हैं, वे सभी के विरुद्ध सक्षम हैं। (वैन रिपर बनाम

संयुक्त राज्य अमेरिका, 13 एफ 2 डी 961, 967 (2 डी सर्कुलर 1926))।"

27. इस प्रकार, साजिशकर्ता सह-साजिशकर्ताओं के बयानों के लिए एजेंसी सिद्धांत पर जिम्मेदार होते हैं, उनके साथीयों द्वारा किए गए प्रकट कृत्यों और अपराधों के लिए जैसे ही होते हैं।"

26) न्यायालय ने राज्य बनाम नलिनी (1999) 5 एससीसी 253 के मामले में पहले के फैसले पर भी गौर किया जिसमें साजिश के कानून को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। उन सिद्धांतों को फैसले के पैरा 32 में पुन: प्रस्तुत किया गया है। हमारे उद्देश्यों के लिए, सिद्धांत संख्या 2 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"2. साजिश के उद्देश्य की प्राप्ति के बाद के कृत्य यह साबित कर सकते हैं कि एक विशेष आरोपी साजिश का पक्ष था। एक बार साजिश

का उद्देश्य हासिल हो जाने के बाद, कोई भी अगला कार्य, जो गैरकानूनी हो सकता है, आरोपी को किसी भगोड़े को आश्रय देने जैसी साजिश का हिस्सा नहीं बनाएगा।

इस प्रकार, जयबीर द्वारा किसी अन्य मामले में किए गए कथित खुलासे/स्वीकारोक्ति बयान (मार्क ए) का कोई परिणाम नहीं होगा।"

27) इसके साथ, अब हम स्कूटर की बरामदगी के साक्ष्य मूल्य पर चर्चा करते हैं।

28) सब-इंस्पेक्टर राम चंदर, जो जांच अधिकारी थे और जो पीडब्लू-17 के रूप में पेश हुए, ने अपने बयान में कहा कि 13 जुलाई 2001 को, जिस स्कूटर का जिक्र है, जिसे अपराध में इस्तेमाल किया गया था, वह इंद्र दलाल के घर से बरामद किया गया था। इसे बरामदे में खड़ी किया गया था और रिकवरी मेमो एक्जिबिट PD के माध्यम से इसे कब्जे में ले लिया गया। यह महत्वपूर्ण है कि 13 जुलाई 2001 को अपीलकर्ता इंद्रा दलाल जेल में थी, क्योंकि उसे 02 जून 2001 को गिरफ्तार किया गया था, जब तथाकथित बरामदगी की गई थी। इस प्रकार, उसकी अनुपस्थिति में बरामदगी की गई। मृतक के भाई हरीश चंदर गोदारा पीडब्लू-2 के रूप में गवाही देने के लिए उपस्थित हुए। उनके मुताबिक, वह घर की छत पर थे, तभी एक लड़के ने आकर उनके भाई पर गोली चला दी। वह ऊपरी मंजिल से नीचे दौड़े और देखा कि लड़का स्कूटर पर शहर की ओर जाते हुए देखा। उन्होंने स्कूटर के नंबर को लिख लिया जिसका नंबर HR 20 G 1102 था

और जो क्रीम रंग का था। उन्होंने आगे बताया कि 13 जुलाई 2001 को, बस स्टैंड के पास पुलिस की गाड़ी देखकर वह केस के बारे में जानकारी लेने पुलिस के पास गए। उसी दौरान एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि इंद्रा दलाल के पुराने घर की दुकान में एचआर 2-0 जी 1102 नंबर का एक स्कूटर खड़ा है। इसे उल्लेखनीय बताना जरूरी है कि जांच अधिकारी (पीडब्लू-17) घटना के तुरंत बाद इंद्रा दलाल के घर गए थे, लेकिन उन्हें वहां कोई स्कूटर नहीं मिला। यदि पीडब्लू-2 ने जांच के दौरान स्कूटर का पंजीकरण नंबर दिया था और जांच अधिकारी इंद्रा दलाल के घर गए थे, तो उस तारीख को वहीं उसी नंबर के साथ खड़े स्कूटर को कैसे नहीं देख पाए। ये सभी तथ्य इंद्रा दलाल के घर से स्कूटर की कथित बरामदगी पर संशय की स्थिति उत्पन्न करते हैं।

29) अपीलकर्ता जयबीर ने इनकार किया है कि प्रश्न में आया स्कूटर उनका है। उनके स्वामित्व को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पंजीकरण क्लर्क गुइब सिंह (पीडब्लू-18) को पेश किया। उन्होंने पुलिस अधिकारी द्वारा दायर किए गए आवेदन (प्रदर्शनी पीजेड) और पवन कुमार द्वारा बनाई गई रिपोर्ट (प्रदर्शनी पीजेड/1) को रिकॉर्ड पर रखा। जयबीर के स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। केवल लिपिक पवन कुमार द्वारा कथित

रूप से रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट ही पेश की गई है, जो प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती। इसके अलावा, पीडब्लू-18 के क्रॉस-एग्जामिनेशन में उन्होंने स्वीकार किया है कि स्वामित्व की प्रासंगिक प्रविष्टि में कटौती की गई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह संबंधित स्कूटर के स्वामित्व परिवर्तन के लिए फॉर्म/आवेदन नहीं लाए थे। उन्होंने आगे बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार, स्कूटर का मूल पंजीकरण विपुल कौशल, पुत्र पृथी सिंह, निवासी हिसार के नाम पर था। स्वामित्व कैसे बदला और जयबीर के नाम पर दर्ज किया गया, इसे साबित करने के लिए आवश्यक सबूत की जरूरत थी। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। इसलिए, हमारा मानना है कि जयबीर के नाम पर स्कूटर के स्वामित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं।

30) उपरोक्त चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि सबूतों की पूरी श्रृंखला या तो साक्ष्य अधिनियम द्वारा निर्मित बाधा के कारण अस्वीकार्य है या फिर अविश्वसनीय/अविश्वासपात्र है। उपरोक्त सभी कारणों से, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 120-बी के तहत की सहायता से इन अपीलकर्ताओं के खिलाफ साजिश के आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और तदनुसार, आक्षेपित निर्णय और सजा को रद्द कर

दिया जाता है। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता इंद्रा दलाल की सजा निलंबित कर दी गई थी। तदनुसार, उसके जमानत बांड निष्प्रभावी हो जाएंगे। अन्य दो अपीलकर्ताओं, बिजेंद्र उर्फ़ विजय और जयबीर को तुरंत जेल से रिहा किया जाएगा, जब तक कि उन्हें किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो।

देविका गुजराल

अपीलों स्वीकार की गई।

यह अनुवाद अर्तिफिसिअल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक **अधिवक्ता नाजिश रशीद** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****